फरीदाबाद

मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 110 अगस्त 1997

अपने बारे में, इस अखबार के बारे में बात करने आप किसी भी दिन मजदूर लाइब्रेरी आ सकते-सकती हैं।

क्यों जानें ? क्या-क्या जानें ? कैसे जानें ? क्या-क्या कर सकते हैं ? (7)

टोलियों की जान : तालमेल और फैलाव

नेता-लीडर : नाकारा के संग-संग नुकसानदायक
अकेले-अकेले : असहाय, लाचार, पाबन्द
भीड़ : खतरे ही खतरे

की हकीकत के दृष्टिगत पाँच-पाँच, सात-सात के समूहों में कदम उठा कर, यानि, टोलियों की राह समस्याओं से निपटने के सन्दर्भ में यह चर्चा आरम्भ हुई थी। काम का बोझा व तीव्रता इस कदर हो गये हैं कि कुछ क्षण ही हमारे अपने बचते हैं। अपने इन क्षणों में हम कार्यस्थल पर अथवा बस्ती में अपनी पसन्द के जिन पाँच-सात लोगों के साथ उठ-बैठ व चर्चायें करते हैं वही टोलियों का आधार है। टोलियाँ हकीकत का वह रूप हैं जो हर एक के हाथ में हैं। टोली में प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार साझेदार बन सकती-सकता है। टोली में बिना किसी के नेतृत्व के सब मिलजुल कर कदम उठा सकते हैं। टोली में अकेले-अकेले की बेचारगी खत्म होती है और साथ-ही-साथ, भीड़ के खतरे से टोली बरी रहती है। टोलियों को शीघ्र प्रभावी और कारगर बनाने के प्रश्न हमारे सामने हैं।

बेचारगी अकेले-अकेले की
= मैनेजमेन्टों के शिकन्जों के लिये आसान शिकार
= बिचौलियों की चरागाह
= अहंकार व डर संग-संग

नेता बेच खाते हैं, लीडर मरवा देते हैं
= हुकुम पर उठते-बैठते, चन्दा देते,
दलदल में धँसते मजदूर।

यह कहना कि **मजदूर मजदूर के पास जायें** फिकरेबाजी लग सकती है। अपने जैसे कमजोरों के पास जाने से क्या होगा जैसे सवालों के जवाब हकीकत की झलक में मिलते हैं।

✓ आमतौर पर फैक्ट्रियों में अपनी समस्या के समाधान के लिय पाँच-सात मजदूर अफसर के पास जाते हैं। अफसर द्वारा अनसुनी करने पर मजदूरों की वह टोली अगर अन्य मजदूरों के सामने अपनी समस्या रखती है और वे मजदूर उस अफसर के पास जाते हैं तब या तो अफसर समस्या का समाधान करे अन्यथा अफसरी खतरे में पड़ जाती है।

✓ किसी फैक्ट्री में कई मजदूरों की कोई समस्या है। मजदूरों की कुछ टोलियाँ समस्या के समाधान के लिये मैनेजर के पास जायें। मैनेजर द्वारा अनसुनी करने पर वे कुछ टोलियाँ अगर अन्य मजदूरों के पास जाती हैं और बड़ी तादाद में वे टोलियों के रूप में मैनेजर के पास जाते हैं तब या तो मैनेजर समस्या का समाधान करे अन्यथा मैनेजरी खतरे में पड़ जाती है।

✓ किसी फैक्ट्री के मजदूरों की बड़ी समस्या है और मैनेजमेन्ट हाथ खड़े कर दे। टोलियों के रूप में उस फैक्ट्री के मजदूर डी. सी. के पास जायें। डी. सी. द्वारा अनसुनी करने पर उस फैक्ट्री के मजदूर टोलियों में अगर अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों के पास जाते हैं और अलग-अलग फैक्ट्रियों के मजदूरों की टोलियाँ डी. सी. के पास जाती हैं तब या तो डी. सी. समस्या का समाधान करे अन्यथा डीसीशिप खतरे में पड़ जाती है।

✓ दूरी की वजह से जहाँ सीधे-सीधे मिलना मुश्किल हो वहाँ खतों के जरिये अपनी समस्या से अन्य स्थानों के मजदूरों को परिचित कराने पर अगर वे मजदूर बडी संख्या में सरकार को विरोध-पत्र भेजते हैं तब या तो सरकार समस्या का समाधान करे अन्यथा अपने पिन्डदान की चिन्ता करे।

खतरे भीड़ के
= मजदूरों के लिये ठन्डे दिमाग से चर्चा का माहौल नहीं;
सोचने का समय नहीं;
अपनी-अपनी बात रखने का अवसर नहीं।
= अफसरों से बातचीत के नाम पर बिचौलियों का जाल
= अफसरों और उनके भाड़े के लोगों के लिये उकसाना व भड़काना आसान
= प्रशासन के लिये पुलिस लाठीचार्ज व फायरिंग की मनमाफिक परिस्थिति
= मजदूरों के बीच दहशत और बिखराव

हकीकत की यह झलक मायुसी के लिये कोई जगह नहीं छोड़ती। चुस्ती-फुर्ती से एक-दूसरे से बातचीत करने, टोलियों द्वारा आपस में तालमेल, अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों से मिलना हमारी समस्याओं का समाधान लिये है। पर्चे-पोस्टरों, गत्तों पर लिख कर शिफ्टों के शुरू व खत्म होते वक्तों पर टोलियों का अलग- अलग सड़कों के किनारों पर खड़ा होना, लन्च के समय टोलियों का गत्तों के साथ विभिन्न फैक्ट्रियों के गेटों पर पहुँचना, मोहल्लों-चाय की दुकानों-शटल ट्रेनों में बातचीत ...... जटिल से जटिल और बड़ी से बड़ी समस्या का शीघ्र व कारगर समाधान करने की क्षमता लिये लगती है। (जारी)

इस अंक की हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट पा रहे हैं। पाँच हजार मजदूर अगर हर महीने एक-एक रुपया दें तो दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

मनचूर इन्डस्ट्रीज

यह कम्पनी 15/4 मथुरा रोड़ पर स्थित है। यहाँ पर सब कुछ ठीक-ठाक से चलता था। हमारा 3 साल का एग्रीमेन्ट इस बार 1 अप्रैल 97 से चालू होना था। लीडरों ने एग्रीमेन्ट के बारे में जनवरी में मीटिंग रखी और कहने लगे कि एम.डी. साहब ने बोला है कि डिमान्ड दो। मजदूरों ने सर्वसम्मति से कह दिया कि दे दो। लीडरों ने माँग-पत्र बनवा कर दे दिया। कम्पनी के मजदूरों ने का. दर्शन सिंह लीडर एडवाइजर के कारनामों के बारे में लीडरों को बताया था कि यह आदमी ठीक नहीं है; इससे बच कर रहना क्योंकि यह हमारे मजदूरों को गलत गाइड करता है; इसने भी मालिक से मिल कर कई बार हमारे मजदूरों का हिसाब दिलवा दिया। परन्तु लीडरों ने नहीं सुना क्योंकि लीड़रों के भी काम बकाया रहते हैं।

यह कम्पनी पहले सैक्टर 24 में प्लाट नं. 270 में थी। अब यह दस नम्बर भट्टा पर है। यहाँ पर कई बार हड़ताल हुई और कई बार लाक आउट हुई। यहाँ पर हर तीन साल के बाद एग्रीमेन्ट होती है। एक बार 91 साल में एग्रीमेन्ट हुआ था। बहुत अच्छा था और सब मजदूर खुश थे। जमादार, माली, पियन, ड्राइवर सहित सब मजदूरों को एग्रीमेन्ट का मुनाफा मिला था। 94 में एग्रीमेन्ट फिर हुआ पर काफी दिन बाद, 7-8 महीने बाद। का. दर्शन सिंह ने खूब अपनी जेब गरम करी। मजदूर यह कहते हैं क्योंकि जब मीटिंग चल रही थी तो एक दिन पार्क में बैठे सभी मजदूरों के सामने बात रखी थी का. दर्शन सिंह ने और मिल कमेटी के लीडरों ने बताया था कि हमारा एम.डी. 200 रुपये बेसिक में, 140 रुपये अलाउन्स में और वर्दी, जूता, साबुन, बोनस में इनक्रीज के लिये राजी है। सब मजदूर खुश हो गये और कहने लगे कि ठीक है। पासा पलट गया दो दिन के बाद, बदल दिया का. दर्शन सिंह ने और होल टाइमर का. द्विवेदी ने जो कि एटक के महान कलाकार लीडर हैं। जनरल सैक्रेट्री महोदय की जेब गरम करी गई और मजदूरों को बताया कि एम.डी. साहब 340 रुपये प्रोडक्शन अलाउन्स देना चाहते हैं। काम के बारे में बताया कि इतना माँगते हैं। लीडरों ने अपने दो भाई पक्के करा दिये और जेब गरम करी का. दर्शन सिंह ने।

अबकी बार फिर एग्रीमेन्ट है। देखते चलिये कि मोड़ किस तरफ मुड़ता है। इस बार भी कमेटी के लीडर अपना धन्धा खूब जमा कर रखे हैं। दो लीडर तो ऐसे हैं कि मैनेजर और परसनल मैनेजर के ही चक्कर काटते रहते हैं। उनके साथ एक भूतपूर्व लीडर है। तीनों मिलकर काम ठेके पर लेते हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मजदूरों को इस बात का पता है, अन्य लीडरों को भी, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं। जब लीडर ही ऐसे काम कर रहे हैं तो मजदूर क्या करें?

माँग-पत्र फरवरी में दिया था। अभी तक कोई बात नहीं हुई। एक मीटिंग रखी थी कमेटी के लीडरों ने। उसमें अनाउन्स किया था कि हम 15.7.97 को काम बन्द कर रहे हैं। कामरेड दर्शन को पता लगा कि मनचूर में काम बन्द होने जा रहा है। उसने मालिक को बताया होगा कि ऐसा होने जा रहा है। फिर उसने लीडरों से कहा कि तुम डिमान्ड नोटिस कोर्ट में डाल दो, कानून से चलो। लीडरों ने उनको कुछ न बोला और लेबर कोर्ट में डाल दिया। अब आप ही बताओ कि जब माँग-पत्र कम्पनी में दिया था तो का. दर्शन ने क्यों नहीं बताया कमेटी के लीडरों को कि एक कापी कोर्ट में दे दो। अब चार महीने हो गये, मजदूर एक्शन में आने लगे तो कामरेड ने उल्टी पट्टी पढ़ा कर कोर्ट में दिलवाया है। मालिक डायरेक्ट फोन करता है का. दर्शन सिंह के पास। कम्पनी के लीडरों को मीटिंग का लैटर मिलता है उससे पहले का. दर्शन सिंह को फोन या लैटर पहुँच गया होता है। अब मजदूरों की जान कामरेड के हाथ में है क्योंकि अन्दर के लीडर तो जो हैं उनके काम तो ठेकों की एक्स्ट्रा कमाई से चलते हैं, वह तो कुछ बोल ही नहीं सकते। प्रधान, सैक्रेट्री साहब कहाँ तक पैर मारें। देखेंगे कि इस बार कौन का भाई पक्का होता है — लीडर एडवाइजर का या कमेटी के किसी लीडर का। तो, लीडर लगे हैं ठेके के चक्कर में। मजदूरों को पता है सब कुछ पर करें क्या?

16.7.97 — मनचूर इन्डस्ट्रीज का एक मजदूर

खानक के खान मजदूर

....तोशाम के निकट खानक की पहाड़ी पर लगे स्टोन क्रैशर, जिनकी संख्या सैंकड़ों है और बढ़ती ही जा रही है तथा मजदूरों की संख्या हजारों है और बढ़ती ही जा रही है, बन्द पड़े रहे हैं। कारण है मजदूरों द्वारा अन्याय के विरूद्ध पत्थर न फोड़ना और सस्ती मजदूरी करने वाले अन्य मजदूरों को पत्थर न फोड़ने देना।

पुराने 20 - 25 वर्ष से काम कर रहे मजदूरों को बेदखल करने के लिये ठेकेदारों की मदद हेतु बन्दूकधारी संगठित गुण्डे आ पहुँचे तो मजदूरों ने गुरिल्ला युद्ध के मोर्चे सम्भाले व पत्थर रूपी गोले उठा लिये। थोड़ा-बहुत प्रसाद खाये व खार खाये पुलिस के खारखास अपने-अपने बिलों में घुस गये। व्यवस्था के संचालक उनसे आगे भागे।

उच्च कमान और उनके प्रिय पुत्र लाख प्रयत्न के पश्चात भी मजदूरों को बहका न सके और डरा न सके।

अन्त में उपायुक्त महोदय ने कहा कि 15 जून तक न मानने पर ठेकेदार पुलिस की सहायता से अपना कब्जा कायम कर लेंगे।

ठीक इसके विपरीत, 22 जून को भारी पुलिस बन्दोबस्त तथा प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में खानक के खान मजदूरों ने पहाड़ों पर अपना कब्जा कर लिया।

वर्तमान व्यवस्था के पक्षधर सभी स्थानीय समाचार पत्रों ने प्रतिदिन समाचार दिये हैं और देते जा रहे हैं।

दूसरी तरफ, ठेकेदार खान मजदूरों को चेतावनी दे रहे हैं कि उनको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है।

इस संघर्ष में लगभग 15 हजार मजदूर रोटी-कपड़े को तरस रहे हैं। खनन उद्योग को 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान उठाना पड़ा है। जरूरतमंदों को रोड़ी क्रैशर तीन गुणा मूल्य पर भी नहीं मिल रहा है। इससे गाँवों व शहरों में मकान निर्माण के काम ठप्प पड़ने से स्थानीय मजदूर — खाती और अन्य लोग बेकार हो गये हैं।

अभी तनाव बना हुआ है........ (25.6.97)

....उपायुक्त महोदय लम्बी छुट्टी पर चले गये हैं......खानक में मजदूरों से खानों के कब्जे नहीं छुड़ा सके....वही मजदूर उन्हीं पहाड़ों में धड़ाधड़ सुरंगें लगा कर पत्थर तोड़ रहे हैं।

25.6. 97 और 5.7.97 — एक अध्यापक

नटराज मशीनरी

बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके पास एक पत्र भेजें। नटराज मशीनरी प्रा.लि., प्लाट न. 66 सैक्टर— 27 सी के मजदूरों की हालत बहुत खराब है। हरियाणा सरकार का भेजा हुआ ग्रेड किसी मजदूर को नहीं दिया जाता। कुछ मजदूरों का फन्ड काटा जाता है। कुल मजदूर 30 रखे हुये हैं। हैल्पर का रेट फिटर और टरनर को भी नहीं मिलता। हैल्पर को सिर्फ 850 रूपये दिये जाते हैं और कोई इसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। मजदूर एक भी नहीं हैं। एक आदमी क्या कर सकता है? मजदूरों में कुछ को वाउचर पर तनखा दी जाती है और कुछ को टिकट लगा कर रजिस्टर पर। लेकिन हरियाणा का रेट किसी को नहीं दिया जाता है।

8.7.97 —नटराज मशीनरी का एक मजदूर

वकील की जुबानी

— श्रम विभाग अधिकारी विवाद को रिजैक्ट करने के लिये मैनेजमेन्ट से कुछ माँग करते हैं।

— विवाद रिजैक्ट करने की जानकारी मजदूर को दी जाती। वरकर हाई कोर्ट जाती-जाता। हाई कोर्ट ने केस लेबर कोर्ट को रेफर करने से इनकार वाले गैर-कानूनी काम के लिये कई बार सरकार को फटकार लगाई और तंग आ कर चेतावनी दे डाली।

— मजदूरों को हाई कोर्ट जाने से रोकने के लिये श्रम विभाग अधिकारी इनकार वाले पत्र अपने डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ा देते हैं लेकिन उन्हें वरकर को भेजते नहीं ! मियाद के बाद अदालत पहुँचने के लिये हाई कोर्ट कानून अनुसार वरकर के खिलाफ आसानी से फैसला दे सकता है...... (जारी)

मैनेजमेन्टों के शिकंजे

मैनेजमेन्टों के लक्ष्य

✂ काम की रफ्तार बढाना ✂ कम मजदूरों से ज्यादा काम करवाना ✂ कम से कम वेतन देना ✂ मजदूरों की मेल-जोल, पहलकदमियों को बिखेरना ✂ नीरस को रंगीन दिखाना ✂ एकताओं की रचना द्वारा मजदूरों में सिरफुटौव्वल करवाना ✂ दहशत का माहौल बनाना ✂ डिसिप्लिन, यानि, मजदूरों पर जकड़ को मजबूत करना ✂ बिना नागा, हर पल काम करवाना, और बेशक अपना–अपना कट-कमीशन सुनिश्चित करना

लूटमार क्लोजर के साथ

विभिन्न कारणों की वजह से जब किसी फैक्ट्री को चलाना मैनेजमेन्ट के लिये लाभदायक नहीं रहता तब फैक्ट्री को बन्द करने से पहले मैनेजमेन्ट खुली लूटपाट पर उतारू हो जाती है। अपने हितों की रक्षा के प्रति जो चौकस नहीं रहते वही इस लूटपाट के अधिक शिकार बनते हैं। अक्सर देखने में आया है कि क्लोजर से पहले मैनेजमेन्टें बकाया वेतन, बकाया बोनस - एल टी ए, बकाया प्रोविडेन्ट फन्ड तथा सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसों के रूप में मजदूरों के करोड़ों रुपये डकार जाती हैं। जिस फैक्ट्री में एक हजार मजदूर होते हैं वहाँ मजदूरों के पन्द्रह-बीस करोड़ रुपये मैनेजमेन्ट इस प्रकार हड़पने की साजिश रचती है।

बकाया वेतन

यूँ तो हर वक्त ही मजदूरों का दस से चालीस दिन का वेतन मैनेजमेन्टों के पास कानूनन रहता है परन्तु कम्पनी के डगमगाने लगने पर मैनेजमेन्टें गैर-कानूनी ढँग से भी मजदूरों का पाँच-छह-बारह-चौदह महीनों का वेतन रोक लेती हैं। इसके लिये लीडरों के साथ एग्रीमेन्टें करना और कानून के खुले उल्लंघन पर आँखें मूँदे रखने के लिये सरकारी अधिकारियों को खुश करना मैनेजमेन्टों का परखा हुआ तरीका है।

बकाया प्रोविडेन्ट फन्ड

अपने हिस्से को जमा करना तो दूर रहा, मजदूरों के वेतन में से काटे पैसों को भी चार-पाँच-छह बरस मैनेजमेन्टें प्रोविडेन्ट फन्ड खाते में जमा नहीं करवाती। वरकरों के पी.एफ. के पैसे हड़पने के लिये सरकारी अधिकारियों को प्रसन्न रखना मैनेजमेन्टों की आजमाई हुई चाल है।

बकाया बोनस, एल.टी.ए. आदि

पाँच-छह साल वर्दी-जूते, साबुन आदि नहीं देने तथा दो-तीन साल बोनस व एल टी ए नहीं देने के लिये लीडरों से और लीडरों के बीच लटके-झटके करवाना मैनेजमेन्टों का अचूक बाण है।

और, सर्विस–ग्रेच्युटी की राशि

पचपन भोग डकारने के बाद तृप्ति के लिये मैनेजमेन्टें राजभोग के तौर पर मजदूरों की बीसियों साल की सर्विस-ग्रेच्युटी की बड़ी राशि निगलती हैं।

लूटपाट-हड़पना-निगलना मैनेजमेन्टों के लिये आसान नहीं है। मजदूरों के विरोध से कदम-कदम पर और हर समय उन्हें निपटना पड़ता है। इसके लिये मैनेजमेन्टों ने कई तरीके विकसित किये हैं।

नम्बर एक : डुगडुगी

मजदूरों को अपने हित में कदम उठाने से रोकने के लिये लीडरी का भ्रमजाल मैनेजमेन्टों की प्रमुख डुगडुगी है। कम्पनी की खराब हालत का रोना, आश्वासन-धमकियाँ, नेगोसियेशन और एग्रीमेन्टों के जरिये लीडर लोग मजदूरों के वेतन आदि की बकाया राशि को बढाते रहते हैं। एक लीडरशिप के मजदूरों में ज्यादा बदनाम होने पर दूसरी लीडरशिप इस भूमिका को हड़प लेती है। फिर तीसरी लीडरशिप.....

नम्बर दो : ढोल

दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। परेशान मजदूर नये नेताओं की अगुआई में फरियादें ले कर सरकारी अधिकारियों के पास जाते हैं। मैनेजमेन्ट को बुला कर साहब रौब-दाब से उसे मजदूरों के सामने हड़काते हैं और समस्या के समाधान का वरकरों को भरोसा दिलाते हैं। विनम्र हो कर मैनेजमेन्टें आवभगत द्वारा सरकारी साँड़ों-खागड़ों को खुश करती हैं। मजदूरों को साहब लोग आश्वासनों की चाशनी चटाने लगते हैं। मामलों को लटका कर, वरकरों की और अधिक रकम मैनेजमेन्टों की झोली में पहुँचा कर सरकारी अधिकारी लाचारी की मुद्रा में हाथ खड़े कर मजदूरों को कोर्ट में जाने की सलाह देते हैं।

नम्बर तीन : बैंड–बाजा

खुली आँखों की धूर्तता पट्टी बँधी आँखों के तराजू में आस जगाती है। कानूनी भाषा का जंजाल और वकीलों की वाकपटुता मजदूरों को पूरी तरह अखाड़े के बाहर धकेल देती है।

1983 में मैनेजमेन्टों द्वारा बन्द की गई **मैटल बॉक्स, डेल्टा टूल्स, ईस्ट इंडिया की जूट मिल** के मामलों पर निगाह डालने पर दिखता है कि पन्द्रह साल की अदालती कार्रवाई के बाद भी

✂ मैटल बॉक्स, डेल्टा टूल्स, ईस्ट इंडिया की जूट मिल के मजदूरों को उनके बकाया वेतन तथा सर्विस-ग्रेच्युटी का एक पैसा भी नहीं मिला है।

✂ इसके विपरीत, इन बन्द फैक्ट्रियों के दर-दर ठोकर खा रहे मजदूरों से लीडरों ने कोर्ट केसों के खर्चे के नाम पर बार-बार चन्दा लिया है।

✂ इन फैक्ट्रियों के मजदूरों का आपस में मिलना भी बन्द हो गया है क्योंकि रोजी-रोटी के लिये वरकर बिखर गये हैं।

1996 के आरम्भ में बन्द की गई **इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड** के मजदूरों को भी अपने बकाया वेतन व सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसों के लिये मैनेजमेन्ट, लीडरों और प्रशासन ने अदालतों की भूल-भुलैया में धकेल दिया है।

विरोध और बदलाव के ठुमके

☺ सरल कदम जो सब मजदूर हर रोज उठा सकते हैं ☺

अनेक बिन्दुओं पर
भिन्न -भिन्न क्षणों में
पाँच-पाँच दस-दस
मजदूरों की टोलियों द्वारा
विभिन्न मुद्दों पर
भिन्न - भिन्न रूपों में
उठाये जाते कदम
अनुशासन - नियन्त्रण -शोषण की चौखटों को
दीमक की तरह चाट जाते हैं।
इसलिये
मजदूरों के लिये यह
सर्वोपरि महत्व के हैं
और इसीलिये
मजदूरों द्वारा खुद उठाये जाते
छोटे-छोटे कदमों को
शिक्षा, दीक्षा और संस्कार
मह[illegible]ान पेश करते हैं।

टूल रूम वरकर

ड्युटी जा रहे एक फैक्ट्री के टूल रूम वरकर ने अखबार लेते समय जल्दी-जल्दी बताया :

"[illegible] रूम के वरकरों को ड्युटी के दौरान औजारों की जरूरत पड़ती है जिन्हें स्टोर से अपने नाम पर इशु करवाना पड़ता है। किसी औजार के गुम हो जाने पर मजदूर के वेतन से पैसे काट लिये जाते हैं। काम भी करो और पैसे भी भरो ! हम लोगों ने एक सरल कदम उठाया है। हम एक औजार से ज्यादा अपने नाम पर इशु नहीं करवाते। औजार की जरूरत पड़ती है और वह पास नहीं होता तब उसे माँगने टूल रूम में दूसरे मजदूर के पास जाना होता है। इससे मनहूस काम से तो दो क्षण छुट्टी मिलती ही है, हमारी आपस में कुछ गपशप भी हो जाती है।"

रात को सोने दो

21 जुलाई को बड़ोदा के एस. एस.जी. अस्पताल में 50 नर्सों ने नाइट शिफ्ट ड्युटी कम करवाने के लिये तीन घन्टे विरोध प्रदर्शन किया।

(बड़ोदा से एक मित्र ने अखबार की कटिंग भेजी है।)

टोलियों की उपलब्धियाँ

जुलाई माह **झालानी टूल्स** मजदूरों की रचनात्मक पहलकदमियों से हलचलों से भरपूर रहा है।

नवम्बर 96 में मजदूरों की एक टोली ने आठ महीनों के बकाया वेतन के लिये एक छोटा व सरल कदम उठाया। उन्होंने चन्दीगढ़ श्रम सचिव को पत्र लिखा। सरकार की धीमी कार्रवाई शुरू हुई और झालानी टूल्स में कार्यरत मजदूरों के बकाया वेतन की राशि बढती गई। चौदह महीनों की तनखा बकाया हो जाने पर मई में टोलियों की संख्या बढी और जून में 15 - 20 टोलियाँ कार्यरत हो गई। टोलियों में मजदूर डी.एल.सी. और डी.सी. के पास अपने बकाया वेतन की वसूली के लिये लिखित में शिकायत करने जाने लगे। 10 जुलाई को मैनेजमेन्ट - लीडर एग्रीमेन्ट की असलियत के कुछ और उजागर होने पर झालानी टूल्स में मजदूरों द्वारा टोलियाँ बनाने तथा कदम उठाने में बहुत तेजी आई। आठ-आठ, दस-दस के समूह में हर रोज पन्द्रह-बीस टोलियाँ डी.एल.सी. और डी.सी. के पास जाने लगी। झालानी टूल्स के दो हजार से ऊपर मजदूर बिना किसी नेतृत्व के अपने सोलह महीनों के बकाया वेतन के लिये कदम उठाने लगे। टोलियों के रूप में सब वरकरों की साझेदारी वाले कदम मजदूरों ने उठाये।

मजदूरों द्वारा स्वयं उठाये छोटे व सरल कदमों से डी.एल.सी. और डी.सी. बौखला गये। 21 जुलाई को डी.सी.ने जिला लोक शिकायत निवारण समिति की मीटिंग के स्थल पर मजदूरों को इकट्ठा कर लीडर पैदा करने की कोशिश की। झालानी टूल्स में कार्यरत दो हजार मजदूरों ने किसी को लीडर बनाने से इनकार कर दिया और टोलियों में अपनी बातें स्वयं रखने पर जोर दिया। प्रशासन ने टोलियों से अलग-अलग बात करने से इनकार कर दिया और बड़ी तादाद में पुलिस बुलाने के बाद एस.डी. एम. ने मजदूरों को भड़काने की कोशिश की। इस पर झालानी टूल्स में कार्यरत मजदूरों ने खुद को बिखेर कर प्रशासन की हिंसा की साजिश को फेल किया।

टोलियों द्वारा अलग-अलग शिकायतें करने के बावजूद उन्हें एक ही तारीख दे कर भीड़ रूप देने में डी.एल.सी. भी जुटे थे। उन्होंने 23 जुलाई को बकाया वेतन की शिकायतों के संग-संग एग्रीमेन्ट खत्म करने के नाम पर दो हजार झालानी टूल्स मजदूरों की भीड़ अपने दफ्तर पर जुटाई। डी.एल.सी. ने एग्रीमेन्ट कैन्सल करने के नाम पर बकाया वेतन के मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया। मजदूरों द्वारा अपने 16 महीनों की बकाया तनखा का मुद्दा सामने रखने पर डी.एल.सी. ने ऊल-जलूल बक कर मजदूरों को हिंसा के लिये भड़काने की कोशिश की और फोन करके पुलिस बुला ली। उकसाने में नहीं आने और वहाँ से हटते देख कर डी.एल.सी. ने एग्रीमेन्ट कैन्सल करने के लिये बातचीत की आड़ में नये लीडर पैदा करने की कोशिश की। झालानी टूल्स मजदूरों ने फिर किसी को लीडर बनाने या मानने से इनकार कर दिया। **एक मजदूर डी.एल.सी. दफ्तर पर कह रहा था, "बातचीत करने में माहिर लोग ही कुर्सी पर बैठते हैं। शिक्षा-दीक्षा अफसरों को बातूनी चिकने घड़े बनाती है। साहबों से बातचीत करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम टोलियों में मधु मक्खियों की तरह इनके चारों तरफ भिनभिना कर इनकी नीन्द हराम करके ही इनसे कुछ हासिल कर सकते हैं।"**

झालानी टूल्स में कार्यरत दो हजार मजदूरों द्वारा टोलियों में उठाये छोटे व सरल कदमों ने बहुत शीघ्र ही डी.एल.सी. को यह कहने को मजबूर कर दिया है कि वह मजदूरों के बकाया वेतन के मामले में कुछ नहीं करेगा। आठ-आठ, दस-दस के छोटे समूहों ने बार-बार डी.सी. के पास जा कर डी. सी. को यह स्पष्ट करने को मजबूर कर दिया है कि वह मजदूरों के सोलह महीनों के बकाया वेतन के लिये कुछ नहीं करेगा। झालानी टूल्स के मजदूरों की टोलियों ने नियम-कानून-संविधान और साहबों के आवरण को कुतर-कुतर कर उनकी मैनेजमेन्ट-पक्षी तथा मजदूर-भक्षी हकीकत को चौक पर ला कर खड़ा कर दिया। वाह ! टोलियों की बात ही कुछ और है !

अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों तक अपनी बातें पहुँचाने के लिये झालानी टूल्स मजदूरों ने खुद एक पर्चा लिखा और बाँटा है। इधर यह मजदूर टोलियों के रूप में अन्य मजदूरों के पास जा कर सरकार पर दबाव डालने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैनेजमेन्टों द्वारा फैक्ट्रियाँ बन्द करते समय बड़े पैमाने पर मजदूरों के बकाया वेतन, प्रोविडेन्ट फन्ड और सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे हड़पने के लिये लीडरों, प्रशासन और बरसों चलती मुकदमेबाजी की त्रिमूर्ति की काट के लिये झालानी टूल्स मजदूर टोलियों में अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों के साथ तालमेल के लिये कदम उठा रहे हैं।

झालानी टूल्स के मजदूरों की टोलियों ने अफसरों के सामने यह महत्वपूर्ण डिमान्ड रखी कि टोलियों के आवेदनों पर सरकारी अधिकारी जो आदेश देते हैं उनकी फोटोकापी प्रत्येक टोली को दी जाये ताकि मजदूरों को पता चले कि अफसर क्या कर रहे हैं।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।